भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

21.09.2020 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1641 का उत्तर

लंबित नई रेल लाइनें

1641. श्री नायब सिंह सैनीः
श्री रवि किशनः
श्री रविन्दर कुशवाहाः
श्री मनोज तिवारीः
श्री संगम लाल गुप्ताः
श्री जॉन बर्लाः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या निधि की कमी और अन्य तकनीकी कारणों से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा पश्चिम बंगाल में नई रेल लाइनों सहित विभिन्न परियोजनाएं लंबे समय से लंबित हैं;
(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने लंबित रेल परियोजनाओं हेतु पर्याप्त निधि आवंटित नहीं की है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;
(ङ) क्या दिल्ली के मीत नगर सबोली रेलवे हाल्ट के पास से गुजरने वाले नाले के निर्माण का कार्य रोक दिया गया है;
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (छ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

Sk

लंबित नई रेल लाइनें के संबंध में दिनांक 21.09.2020 को लोक सभा श्री नायब सिंह सैनी, श्री रवि किशन, श्री रविन्दर कुशवाहा, श्री मनोज तिवारी, श्री संगम लाल गुप्ता और श्री जॉन बर्ला के अतारांकित प्रश्न सं. 1641 के भाग (क) से (छ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) और (ख): जी नहीं। रेलवे परियोजनाएं ज़ोनल रेलवे - वार स्वीकृत की जाती हैं न कि राज्य-वार, क्योंकि रेलवे नेटवर्क विभिन्न राज्यों की सीमाओं के आर-पार फैला हुआ है। 01.04.2020 की स्थिति के अनुसार, दिल्ली/एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में पूर्ण रूप से/आंशिक रूप से पड़ने वाली 53,039 किमी कुल लंबाई को कवर करने वाली 513 परियोजनाएं (189 नई लाइनें, 54 आमान परिवर्तन और 270 दोहरीकरण) योजना/स्वीकृति/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से, 10,013 किमी लंबाई को पूरा कर लिया गया है और मार्च, 2020 तक 1.86 लाख करोड़ रु. का व्यय किया गया है।

लागत, व्यय और परिव्यय सहित परियोजनाओं का ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट अर्थात् >Ministry of Railways >Railway Board >About Indian Railways >Railway Board Directorates >Finance (Budget)>Pink book (year) Railway-wise Works Machinery & Rolling Stock Programme (RSP) पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है।

2014-19 के दौरान, भारतीय रेल पर कुल 13,124 किमी लंबाई (नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण) को यातायात के लिए खोल दिया गया है जो 2009-14 (7,599 किमी) से 73% अधिक है।

किसी भी परियोजना (परियोजनाओं) का समय से पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के प्राधिकारियों द्वारा वन संबंधी स्वीकृति, उल्लंघनकारी उपयोगिताओं का अंतरण, विभिन्न प्राधिकारियों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना साइट के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए परियोजना विशेष साइट के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और ये सभी कारक परियोजना दर परियोजना भिन्न होते हैं तथा परियोजना (परियोजनाओं) के निष्पादन-समय को प्रभावित करते हैं।

(ग) और (घ): 2014-19 के दौरान, भारतीय रेल पर नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए औसत वार्षिक व्यय 11,527 करोड़ रुपए प्रति वर्ष (2009-

14 के दौरान) से बढ़ाकर 26,026 करोड़ रुपए प्रति वर्ष किया गया है, जो 2009-14 से 126% अधिक है। 2019-20 के दौरान व्यय बढ़कर 39,836 करोड़ रु. हो गया है जो 2009-14 के औसत वार्षिक व्यय से 246% अधिक है और किसी भी वित्त वर्ष से अब तक का सबसे अधिक व्यय है।

(ङ) से (छ): जी हां। वजीराबाद और उत्तर प्रदेश बार्डर के बीच आरसीसी ओपन ड्रेन का निर्माण कार्य 3.00 करोड़ रु. की लागत से रेलवे और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीएलएडी) निधि के बीच 50:50 लागत भागीदारी आधार पर आपसी सहमति से हुआ था। कार्यकारी अभियंता योजना, पूर्व दिल्ली नगर निगम ने 1.50 करोड़ रु. की अपनी हिस्सेदारी में से दिनांक 05.05.2020 के पत्र के तहत 1,12,04,879/- रु. की राशि जारी की। हालांकि, तत्पश्चात दिनांक 21.08.2020 के पत्र के तहत आबंटित राशि को रद्द कर दिया गया है। इसलिए, कार्य शुरू नहीं किया जा सका, क्योंकि पर्याप्त राशि समय पर जारी नहीं की गई थी।

******

Sk